अदम्य साहस की प्रतिमूर्ति एवं मराठा साम्राज्य के महान सेनापति पेशवा बाजीराव जी प्रथम की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि।

—— ब्रजेश पाठक,डिप्टी सीएम, उप्र

केंद्रशासित राज्यों में भी योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

—— नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री

निगम के प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को मिलेगी मोबाइल लाइब्रेरी की सुविधा

नई दिल्ली (एसएनबी)। सीड्स और चेग इंडिया ने आपसी सहयोग से चेग द्वारा विकसित 'एजुकेशन बियॉन्ड स्कूल्स अवधारणा पर आधारित राजधानी में प्राइमरी स्कूल की शिक्षा को एक नए प्रारूप देने के लिए विशेष पहल की शुरुआत की है। बस में स्थापित मोबाइल लाइब्रेरी दिल्ली नगर निगम के स्कूलों के प्राइमरी सेक्शन के छात्रों को इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करेगी। मोबाइल लाइब्रेरी बस का उद्घाटन निगम में शिक्षा विभाग के निदेशक की उपस्थिति में विश्वकर्मा नगर स्थित नगर निगम स्कूलों में हुआ। इस अवसर पर चेग इंडिया के प्रबंध निदेशक विजय टीएस, सीड्स के सह-संस्थापक मनु गुप्ता सह-संस्थापक, कई शिक्षक और अधिकारी उपस्थित थे।

चेग इंडिया के प्रबंध निदेशक विजय टीएस ने कहा कि मोबाइल लाइब्रेरी बस एक इनोवेटिव पहल है, जो न केवल शिक्षा के तरीके में नए बदलाव लाएगी, बल्कि क्वालिटी एजुकेशन तक बच्चों की पहुंच को बढ़ाएगी। सीड्स के साथ साझेदारी करके हम दिल्ली में सरकारी स्कूल के छात्रों को इंटरैक्टिव डिजिटल सामग्री और उन्नत शिक्षण प्रणाली के माध्यम से सशक्त बना रहे हैं। हमारी यह पहल अन्य संस्थानों को भी भारत के युवाओं की शिक्षा में निवेश करने के लिए प्रेरित करेगी।

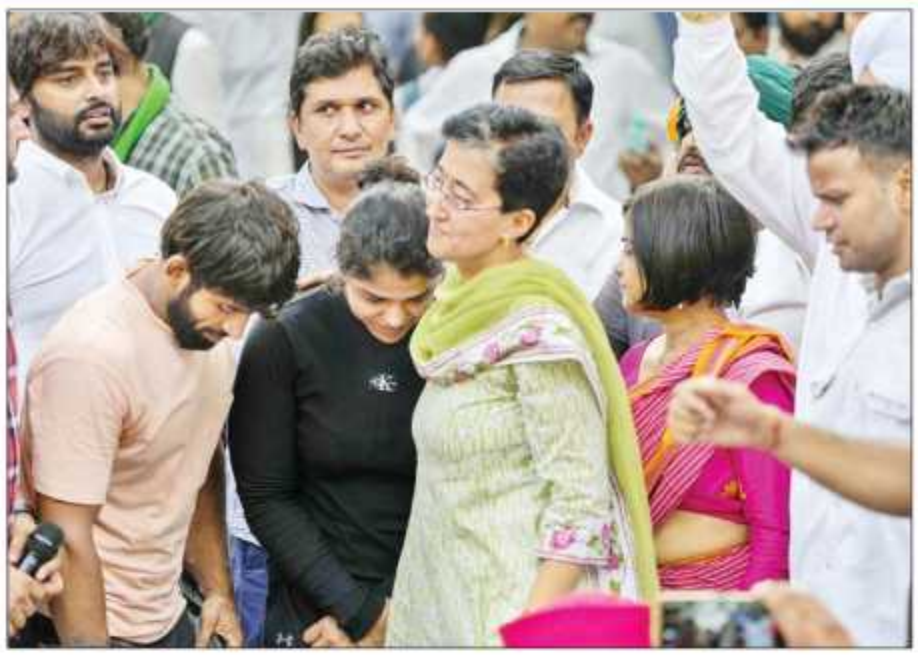

जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के समर्थन के लिए शुक्रवार को पहुंची दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी व सौरभ भारद्वाज। फोटो : प्रेट

साल के आखिर तक दिल्ली को मिल जाएंगे चार नए फ्लाई ओवर : आतिशी

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को राजधानी में निर्माणाधीन फ्लाई ओवरों एवं मौजूदा फ्लाई ओवरों के रख-रखाव को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि इस साल के अंत तक राजधानी के लोगों को 4 नए फ्लाई ओवर एवं दो अंडरपास मिल जाएंगे। इससे लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी और वाहन चालकों को सुगम यात्रा का अहसास होगा। निर्माणाधीन चार फ्लाई ओवरों में सराय काले खां टी-जंक्शन, पंजाबी बाग-राजा गार्डन फ्लाई ओवर का विस्तार, आनंद विहार-अप्सरा बॉर्डर के बीच एवं यमुना विहार का डबल डेकर फ्लाईओवर शामिल हैं। बैठक में 12 से अधिक फ्लाईओवरों के रख-रखाव को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की।

पीडब्ल्यूडी मंत्री ने बताया कि लोगों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए विभाग मुख्यमंत्री के विजन पर काम कर रहा है। यह प्रोजेक्ट पूरे होने पर रोजाना लाखों वाहनों को जाम से छुटकारा मिलेगा। बैठक में उन्होंने अधिकारियों से निर्धारित समय सीमा का ध्यान रखते हुए काम करने को कहा है। उन्होंने अधिकारियों को हर महीने प्रगति रिपोर्ट देने को कहा है। उन्होंने बताया कि पंजाबी बाग से राजा गार्डन तक फ्लाई ओवर के विस्तार का काम चल रहा है। दोनों फ्लाई ओवर की 1-1 लेन को बढ़ाकर 3 लेन का किया जाएगा और 3-3 लेन के दो नए फ्लाई ओवर बनाए जाएंगे। पंजाबी बाग से राजा गार्डन तक 1400 मीटर तक विस्तार किया जाएगा।

- निर्माणाधीन एवं मौजूदा फ्लाई ओवरों के रख-रखाव को लेकर समीक्षा बैठक
- टाइम लाइन के साथ काम करें अधिकारी

इन फ्लाई ओवरों पर यातायात का काफी बोझ है। यहां रोहतक रोड (एनएच -10) से हरियाणा की तरफ से काफी वाहन आते हैं। यह फ्लाई ओवर उत्तरी दिल्ली को दक्षिणी दिल्ली, गुडगांव एवं एनसीआर के अन्य हिस्से से जोड़ने का काम करता है। आनंद विहार और अप्सरा बॉर्डर के बीच छह लेन के फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है। करीब 1440 मीटर लंबा यह फ्लाई ओवर रामप्रस्थ कॉलोनी, विवेक विहार और श्रेष्ठ विहार रेड लाइट पर लगने वाले जाम की समस्या से लोगों को मुक्ति दिलाएगा। यहां औसतन रोजना 1.48 लाख वाहन गुजरेंगे। करावल नगर, घोंडा-बृजपुरी जंक्शन पर डबल डेकर फ्लाईओवर उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में यमुना विहार व भजनपुरा के बीच यातायात को सुगम बनाएगा। 1.4 किमी लंबा यह फ्लाई ओवर साल के आखिर तक बनकर तैयार हो जाएगा। 2 नए अंडरपास का चल रहा काम : प्रगति मैदान कॉरिडोर प्रोजेक्ट का अधिकतम काम पूरा हो चुका है। यहां निर्माणाधीन अंडरपास का काम जुलाई तक पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही मुकरबा चौक अंडरपास बादली से हैदरपुर जाने की दिशा में निर्माण कराया जा रहा है। यह अंडरपास करीब 1.5 किलोमीटर लंबा होगा।

सिसोदिया को जमानत न मिलना, जांच एजेंसियों के पास पक्के सबूत : सचदेवा

नई दिल्ली (एसएनबी)। उप-मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया की एक बार फिर जमानत याचिका रद्द होने पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि इससे साबित होता है कि जांच एजेंसियों के पास उनके विरुद्ध मजबूत साक्ष्य हैं। यही वजह है कि सिसोदिया के बड़े-बड़े वकील भी उन्हें जमानत दिलाने में नाकाम रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल उठाते हुए कहा है कि लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इतने बड़े-बड़े वकील लगाने के बाद भी सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है। मुख्यमंत्री के इस दावे की हवा निकल गई है। उन्होंने कहा कि सिसोदिया का भी मामला कमोवेश सत्येंद्र जैन से मिलता है। सत्तारूढ़ आप नेताओं ने सत्येंद्र के बारे में बात करनी भी बंद कर दी है।

जंतर-मंतर के संरक्षण के लिए समिति गठित

नई दिल्ली (एसएनबी)। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने हाईकोर्ट को बताया कि यहां जंतर-मंतर वेधशाला के संरक्षण, जीर्णोद्धार और समुचित संचालन के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। इसपर कोर्ट ने कहा कि उसे उम्मीद है कि स्मारक के संरक्षण, जीर्णोद्धार और समुचित संचालन को लेकर समिति जल्द ही कदम उठाएगी और बैठक आयोजित करेगी। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने इसको लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी देने को कहते हुए सुनवाई 31 अगस्त के लिए स्थगित कर दी। साथ ही अधीक्षण पुरातत्वविद् को अगली सुनवाई के दिन उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। कोर्ट का यह आदेश उसके सितंबर, 2010 आदेश का पालन न करने को लेकर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने वाली अवमानना याचिका पर आया है। एएसआई ने शपथ पत्र देकर कहा था कि जंतर-मंतर के मूल गौरव को बहाल किया जाएगा।

अदालती टिप्पणी से आत्मसम्मान पर पड़ता है गहरा असर : हाईकोर्ट

■ अमरेश कुमार

नई दिल्ली। एसएनबी

- सीबीआई के अधिकारियों के खिलाफ निचली अदालत की टिप्पणी को किया निरस्त
- निचली अदालत ने सीबीआई पर 16 हजार का हर्जाना भी लगाया था
- सीबीआई अधिकारियों की कार्य क्षमता का आकलन करना पूरी तरह से अनुचित : हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अदालती आदेश के माध्यम से किसी का अपमान व अनादर किए जाने से उसके आत्मसम्मान और समाज में उसकी प्रतिष्ठा पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अदालती आदेश सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। ऐसी दशा में अदालतों को इस तरह की निंदा करने से बचना चाहिए। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने यह बात केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों के कामकाज को लेकर निचली अदालत की टिप्पणियों को खारिज करते हुए की। निचली अदालत ने सीबीआई पर 16 हजार रुपए का हर्जाना भी लगाया था। यह हर्जाना आरोपियों के बयान दर्ज करने का मसौदा प्रश्न तैयार करने एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहने को लेकर लगाया गया था।

न्यायमूर्ति ने कहा कि प्रश्न तैयार करना अदालत का ही काम है। एक बेहतर न्यायाधीश वह है, जो साक्ष्यों में से आपत्तिजनक सबूत खोजे और उसके बारे में अभियुक्त से स्पष्टीकरण मांगे। एक न्यायाधीश ही जान सकता है कि क्या अपराध बनता है या नहीं। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति की काम करने की क्षमता, विशेषज्ञता या वैधता को अदालत को अपने ऊपर नहीं लिया जाना चाहिए और किसी भी नाराजगी और असहमति की दशा में सम्मानजनक, संयमित और विनम्र तरीके से प्रतिक्रिया को व्यक्त किया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति ने कहा कि यह अदालत यह समझ पाने में विफल रही है कि धमकी के रूप में चेतावनी को कैसे न्यायिक आदेश का हिस्सा बनाया जा सकता है, क्योंकि यह काफी गंभीर प्रकृति की होती है। इसे पारित करते समय संबंधित व्यक्ति या जांच एजेंसी के आचरण की गंभीरता से जांच की जानी चाहिए और उसके बाद सावधानी के साथ अदालती टिप्पणी की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति ने निचली अदालत के 5 मार्च, 2018 के आदेश में सीबीआई के खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि सीबीआई अधिकारियों की कार्य क्षमता का आकलन करना पूरी तरह से अनुचित है। उस पर से उसके निदेशक एवं डीओपी से यह कहना कि वे अपनी क्षमता का आकलन करें। उन्होंने कहा कि अगर अंग्रेजी में तैयार प्रश्नावली के वाक्य असंतोषजनक पाए गए तो अदालत को ध्यान देना चाहिए कि अंग्रेजी मसौदा तैयार करने वाले अधिकारियों की मातृभाषा नहीं है। सभी अंग्रेजी भाषाविदों की तरह लिखने एवं बोलने में कुशल नहीं हो सकते। हालांकि राजधानी की अदालतों में अंग्रेजी का उपयोग किया जाता है, लेकिन किसी अदालत या प्राधिकरण को उस भाषा में प्रश्नों को उचित ढंग से नहीं लिखने वालों को दोषी ठहराने का अधिकार नहीं देता है।

नेपाली दुष्कर्म पीड़िता को मिली 27 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली हाईकोर्ट ने नेपाल की एक नाबालिग बलात्कार पीड़िता को 27 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति प्रतिभा मनिंदर सिंह ने कहा कि पीड़िता व उसका परिवार नेपाल के नागरिक हैं, इस दशा में एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टर जल्द से जल्द उसका गर्भ समाप्त करने के लिए कदम उठाएं। उस दौरान मेडिकल टीम यह सुनिश्चित करे कि नाबालिग की बेहतर देखभाल हो और उसके बाद भी उसकी देखभाल की जाए, ताकि वह जल्द ठीक हो जाए। उसके बाद ही उसे अस्पताल से छुट्टी दी जाए। परिवार ने कोर्ट को आश्वास्त किया कि अगर बच्चा जीवित पैदा होता है, तो वह उसकी उचित देखभाल करेंगे।

अदालत पीड़िता की मां की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने अपनी नाबालिग बेटी का गर्भपात कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। मां ने कहा था कि नेपाल में उसकी बेटी के साथ पिछले साल सामूहिक बलात्कार किया गया था। उस समय वह और उसका पति दिल्ली में काम कर रहे थे।

कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 27, बीकेसी, सी–27, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051
शाखा कार्यालय : 1/11, प्रथम तल, पूर्वी पटेल नगर, नई दिल्ली –110 008 कॉर्पोरेट पहचान संख्या – L65110MH1985PLCO38137

अचल सम्पत्तियों की ई–नीलामी बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के साथ पठित नियम 9 (1) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार (रों), गारंटर (रों) और/या कानकर्ता (ओं) को सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ('प्रतिभूत लेनदार') को बंधक/प्रभारित की गई है, जिसका नैतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 27–01–2022 को लिया जा चुका है, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार, की कर्जदार/तों नामत **मैसर्स पेट्रोल्यूब इंडिया लिमिटेड, प्रधान कर्जदार अब परिसमापनाधीन – इसके परिसमापक श्री ए.के. गुप्ता और (1) श्री हरि राम गुप्ता (पूर्व निदेशक), (2) श्री अर्पित गुप्ता (पूर्व निदेशक), (3) श्री प्रतीक गुप्ता (पूर्व निदेशक)** की तरफ **31–08–2017** तक बकाया रु. **22,45,90,166/–** (रुपए बाईस करोड़ पैंतालीस लाख नब्बे हजार एक सौ अड़सठ मात्र) भुगतान/वसूली तक आगे चक्रवृद्धि आधार पर संविदात्मक दर पर ब्याज और अन्य प्रभारों की वसूली के लिए दिनांक **15 मई, 2023** को ई–नीलामी के माध्यम से **"जैसा है जहां है आधार", "जो है जैसा है आधार"** और **"जो कुछ भी है वहां है आधार"** पर बेची जाएगी।

बंधकदाता/ओं का नाम	ई–नीलामी हेतु प्रस्तुत अचल/चल सम्पत्ति का विस्तृत विवरण	सुरक्षित मूल्य आईएनआर)/डरोहर राशि जमा
मैसर्स पेट्रोल्यूब इंडिया लिमिटेड, (परिसमापनाधीन)	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : औद्योगिक सम्पत्ति सं. 19/3 खसरा नंबर 19/3 का भाग, ग्राम कनहरुद्दीन नगर, नागलोई, दिल्ली–110041 में जमा न्यू राम नगर के नाम से ज्ञात कालोनी में स्थित है, कुल **परिमाप 260 वर्ग गज** के मुख्तह पर निर्मित सुपरस्ट्रक्चर सहित।	रु. 69,38,000/– (रुपए उनहत्तर लाख आठ हजार मात्र) / रु. 6,93,800/– (रुपए छह लाख नब्बे हजार आठ सौ

कर्जदार/गारंटर अपने पूर्ण विवेक पर और सम्बंधित प्रतिभूति के पूर्व अनुमोदन पर, उक्त सम्पत्ति के निरीक्षण की व्यवस्था, अपने अधिकृत प्रतिनिधि/एजेंट के माध्यम से 12 मई, 2023 को अपराह्न 03.00 घंटे से अपराह्न 5.00 बजे तक के बीच कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण नियम और शर्तें :

1. ई–नीलामी केवल 'ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली' के माध्यम से वेबसाइट www.bankeauctions.com के माध्यम से 12 मई, 2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक के बीच, 5 मिनट प्रत्येक की अवधि के असीमित विस्तार के साथ, आयोजित की जाएगी। ई–नीलामी के बारे में विवरण के लिए इच्छुक बोलीदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्रा. लिमिटेड, तृतीय तल, प्लॉट नंबर 68, सेक्टर–44, गुरुग्राम, हरियाणा से सम्पर्क कर सकते हैं, सम्पर्क व्यक्ति **श्री विनोद चौहान – 98138–87931, ईमेल : delhi@clindia.com और support@bankeauctions.com, हेल्पलाइन नंबर 91–124 4302020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024, सपोर्ट मोबाइल नंबर + 91–7291981124 / 25 / 26.**
2. इच्छुक बोलीदाता नीलामी विवरण और बिक्री के नियम और शर्तों के लिए बैंक की आधिकारिक वेबसाइट–https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html और/या https://auctions.kotak.com पर जा सकते हैं।
3. नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, बोलीदाताओं को पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर जाने की सलाह दी जाती है और बोली प्रक्रिया में भाग लेने वाले बोलीदाताओं के लिए उक्त नियम और शर्तें बाध्यकारी होंगी।
4. यह अनुरोध किया जाता है कि इच्छुक बोलीदाताओं को बोली और अन्य दस्तावेज अपलोड करने से पहले पोर्टल https://www.bankeauctions.com से लॉगइन आईडी और पासवर्ड जनरेट करना आवश्यक है।
5. बोली प्रपत्र निर्धारित प्रपत्र में भरा जाना है और केवल बोलीदाता के केवाईसी दस्तावेजों के साथ पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर 11 मई, 2023 तक या उससे पहले 4.00 अपराह्न तक ऑनलाइन अपलोड किया जाना है, और विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित बोली दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां और बोलीदाताओं के केवाईसी उनमोडिफाएबल, फ्लाटामुक्त और अपलाडमेंत/ग्राह्यमुक्त पर मेल द्वारा भेजे जाने चाहिए। बोलीदाता को ईमेल का विषय **"मैसर्स पेट्रोल्यूब इंडिया लिमिटेड के खाते में संपत्ति के क्रय हेतु"** लिखना चाहिए।
6. संभावित बोलीदाता, मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से लॉगइन आईडी और पासवर्ड बनाने और ऑनलाइन बोली प्रक्रिया आदि के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण उपरोक्त नंबरों पर प्राप्त कर सकते हैं।
7. धरोहर राशि जमा (ईएमडी) आरटीजीएस/एनईएफटी/निधि अंतरण के माध्यम से **खाता संख्या 0641010252720001, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, नरीमन पॉइंट शाखा, मुंबई, आईएफएससी कोड : KKBK0000958,** में 11 मई, 2023 को या उससे पहले शाम 04.00 बजे तक जमा करनी होगी। आरटीजीएस/एनईएफटी/निधि अंतरण केवल इच्छुक बोलीदाताओं के खातों से ही किया जाएगा। किसी तकनीकी गड़बड़ी के कारण ईएमडी और में जमा करने में या निर्धारित समय सीमा के भीतर बोली दस्तावेज जमा करने में देरी के मामले में अधिकृत अधिकारी, अधिकतम बोली गारंटीदाता और परस्पर बोली प्रक्रिया, अपने विवेकाधिकार पर और उसकी संतुष्टि पर, किसी भी व्यक्ति को कोई प्रकटीकरण दिए बिना निर्धारित कटऑफ समय के बाद प्राप्त बोली को स्वीकार कर सकते हैं। ईएमडी राशि जमा किए बिना जमा की गई कोई भी बोली स्वत: निरस्त मानी जाएगी। प्रस्तावित बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
8. प्रस्तुत की जाने वाली बोली मूल्य सुरक्षित मूल्य के बराबर और/या उससे अधिक होगी और बोली प्रक्रिया के दौरान, बोली लगाने वाले बोलीदाताओं को अपनी बोली रुपये 1,00,000/– (रुपये एक लाख मात्र) के गुणकों में बढ़ानी होगी।
9. यदि कोई बोली ई–नीलामी कार्यवाही के समापन समय से अंतिम 5 मिनट की मीतर रखी जाती है, तो समापन समय स्वचालित रूप से और तुरंत 5 मिनट तक बढ़ा दिया जाएगा जैसा कि ऊपर बताया गया है।
10. सफल बोलीदाता को उपखात बोली राशि का 25 (पहले से भुगतान की गई ईएमडी सहित) ई–नीलामी बिक्री की कार्यवाही बंद होने पर या ई–नीलामी के दिन व्यावसायिक घंटे बंद होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस पर ऊपर निर्धारित गेड में जमा करना होगा। उपखात बोली राशि का शेष 75% उस तारीख से 15 दिनों, जिस दिन ऐसे सफल बोलीदाता को बिक्री की स्वीकृति/पुष्टि की जाती है या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जमा करना होगा, जो अधिकृत अधिकारी के विवेकाधिकार पर और सरफेसी अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति हित नियमावली, 2002 के प्रावधानों के भीतर होगी। कृपया ध्यान दें कि बिक्री प्रतिकल के भुगतान के लिए समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी और सफल नीलामी खरीदार की इच्छा या दैवीय आपदा के आधार पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा, यदि वह किसी भी कारण से निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है।
11. उपखात बोली लगाने वाले का संपत्ति पर तब तक कोई अधिकार और हक नहीं होगा जब तक कि उसके पक्ष में बिक्री प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है, जो संपूर्ण नीलामी मूल्य और अन्य आवश्यक खर्चों की वसूली के अधीन है। बिक्री ई–नीलामी के नियमों और शर्तों के अधीन होगी और उक्त प्रभाव के लिए सुरक्षित लेनदार द्वारा पुष्टि की जाएगी।
12. यदि सफल बोलीदाता पूरी बोली/नीलामी राशि जमा करने में विफल रहता है, तो सफल बोलीदाता द्वारा पहले ही जमा की गई राशि को जब्त कर लिया जाएगा और सुरक्षित बोलीदाता का न तो कोई दावा और न ही जमा की गई राशि पर ब्याज होगा। प्राधिकृत अधिकारी नीलामी संपत्ति/संपत्तियों के संबंध में सरफेसी ऐक्ट, 2002 और प्रतिभूति हित नियमावली, 2002 के प्रावधानों के अनुसार उसे उपलब्ध किसी एक या अधिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।
13. उपरोक्त वर्णित निर्धारित अवधि के भीतर संपूर्ण बिक्री प्रतिफल प्राप्त होने पर, अधिकृत अधिकारी बिक्री प्रमाण पत्र जारी करेगा, उसके बाद बिक्री पूरी हो जाएगी और उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा।
14. बिक्री प्रमाण पत्र उसी नाम से जारी किया जाएगा जिसमें बोली जमा की गई है। बोली में उल्लिखित किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) के नामों को बिक्री प्रमाण पत्र में शामिल/प्रतिस्थापन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
15. असफल बोलीदाताओं को ईएमडी राशि, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड द्वारा उनके खातों में आरटीजीएस/एनईएफटी/फंड ट्रांसफर के माध्यम से, 10 (दस) कार्य दिवसों के भीतर और बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
16. अधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या अतिरिक्त ई–नीलामी बिक्री को स्थगित/रद्द करने का पूर्ण अधिकार है। बोली जमा करने के बाद ई–नीलामी बिक्री के स्थगित/रद्द करने की स्थिति में, बोलीदाताओं द्वारा जमा की गई ईएमडी बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी और यदि बोलियां खारिज कर दी जाती हैं, तो अधिकृत अधिकारी, निजी संधि द्वारा संपत्ति की बिक्री के लिए, किसी भी बोलीदाता या अन्य पार्टियों के साथ बातचीत कर सकता है।
17. यदि कोई बोलीदाता नीलामी के तहत 1 से अधिक सम्पत्ति के लिए बोली लगाने का इच्छुक है, तो बोलीदाता को उपरिवर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए हर सम्पत्ति के लिए अलग बोली प्रस्तुत करनी होगी।
18. ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विवरण अधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार की सर्वोत्तम जानकारी के लिए दिया गया है, लेकिन अधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार इस उद्घोषणा में किसी भी चूक, गलत विवरण या छूट के लिए जवाबदेह नहीं होंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि, यह निमंत्रण सम्भावित बोलीदाताओं को आमंत्रित करने के लिए है और नीलामी को प्रभावित करने के लिए अधिकृत अधिकारी या कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड की ओर से किसी भी प्रकार का वचनकारी तात्पित नहीं बनाता है। प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए और बिना किसी पूर्वसूचना के प्रक्रिया को रद्द या संशोधित करने और/या स्वीकार नहीं करने और/या बिक्री की इच्छुक पार्टी/सम्भावित निवेशक/बोलीदाता को आयोजन प्रक्रिया करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
19. बैंक को (क) माननीय एनसीएलटी, दिल्ली के समक्ष सं. दाखिका सं. (आईबी) –343 (एनडी)/2017, (ख) माननीय ऋण वसूली न्यायाधिकरण–I, दिल्ली के समक्ष एसए सं. 346/2021, (ग) एसए सं. 80/2021, (घ) माननीय ऋण वसूली न्यायाधिकरण–I, दिल्ली के समक्ष एसए सं. 74/2019, को लंबित होने के अतिरिक्त किसी ऋणभार की जानकारी नहीं है। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे स्थानीय प्राधिकरण की बकाया राशि अर्थात नगरपालिका कर, स्थलकर/सोसाइटी शुल्क, बिजली और पानी के शुल्क और इसी प्रकार सहित किसी भी अन्य बकाया या करों के संबंध में स्वतंत्र जांच करें। प्राधिकृत अधिकारी या बैंक नीलाम की गई संपत्ति के संबंध में सरकार या किसी अन्य व्यक्ति के किसी भी शुल्क, एहसानिकार, भार या किसी अन्य देय राशि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर की बकाया, बिजली बकाया आदि सहित संपत्ति पर भार के संबंध में अपनी स्वतंत्र जांच करें। यदि नीलामी प्रक्रिया के बाद, किसी प्रमाणपत्र पंजीकरण और कब्जा इस्तांतरण तक किसी भी समय, बैंक को आगे कार्यवाही की बनाती, किंतु उसी तक सीमित नहीं, का आदेश किया जाता है, तो बैंक अब तक जमा किया जा चुका धन अपने विवेक के आधार पर, सम्पत्ति की बिक्री के मिलाया जमा की जा चुकी राशि बिना किसी ब्याज तथा/अथवा क्षतिपूर्ति तथा/अथवा दावों के वापस करेगा।
20. यदि बोली लगाने वाले को ई–नीलामी बिक्री में सफल बोलीदाता घोषित किया जाता है और उसके बाद, यदि नीलामी की कार्यवाही किसी भी न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा, बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने और कब्जा सौंपने तक किसी भी स्तर पर रोक दी जाती है, जिसमें बैंक को आगे की कार्यवाही से रोकना शामिल है, तो बोलीदाता को पास उसके द्वारा जमा की गई ईएमडी/राशि या संपत्ति की बिक्री के लिए जमा की गई राशि पर किसी भी ब्याज की वापसी का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। बैंक अपने विवेकाधिकार पर बिना किसी ब्याज और/या हर्जाने और/या दावों के जमा की गई अमनराशि वापस कर देगा और किसी भी प्रकार के सत्कार पर विचार नहीं किया जाएगा।
21. मनोरंजन शुल्क, स्टांप शुल्क, कर आदि सहित सभी वैधानिक देय/अन्य देय राशि खेता को वहन करनी होगी।
22. वर्तमान नोटिस को तहत नीलामी–सह–बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के संबंध में सभी आउटगोइंग शुल्क यानी नगरपालिका कर, स्थलकर/सोसाइटी शुल्क बिजली और पानी के शुल्क और किसी भी अन्य बकाया का करों का भुगतान नीलामी खरीदार द्वारा ही किया जाएगा।
23. अन्य सभी आकस्मिक शुल्क (वर्तमान नीलामी के तहत संपत्ति के संचालन के लिए सुरक्षा शुल्क या स्थलकर शुल्क सहित लेकिन सीमित नहीं) बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से उपखात बोली लगाने वाले द्वारा वहन किया जाएगा, जिसे बिक्री प्रमाण पत्र के पंजीकरण से पहले बैंक को अदा/क्षतिपूर्ति करनी होगी। तात्पर्य, प्राधिकृत अधिकारी के विवेकाधिकार पर, महिला के लिए कोई मिसाल कायम किए बिना, किसी भी न्यायालय और तर्कसंगत देरी को छूट के लिए माना जाएगा।
24. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194–ए के अनुसार, यदि बिक्री प्रतिफल रु. 50,00,000 (पचास लाख रुपये मात्र) और उससे अधिक है, तो बिक्री से प्राप्त राशि पर टीडीएस लागू होगा। सफल बोलीदाता/खरीदार बिक्री मूल्य से काटक रखने वाले मैसर्स पेट्रोल्यूब इंडिया लिमिटेड के पैन नंबर– AAACP7805M से लागू टीडीएस (1%) काटकर जमा करेगा और उसे आयकर विभाग के पास जमा करेगा। इसके अलावा, बिक्री मूल्य का केवल 99% बैंक को प्रेषित किया जाना है। सफल बोलीदाता/क्रेता के पक्ष में बैंक द्वारा बिक्री प्रमाण पत्र केवल फॉर्म 16बी, फॉर्म 26क्यूबी और ऐसे टीडीएस की जमा राशि के सत्यापन के प्राप्त होने पर जारी किया जाएगा।
25. ई–नीलामी **"जैसा है जहां है आधार", "जैसा है जैसा है आधार" और "जो कुछ भी है आधार"** यहीं उल्लिखित नियमों और शर्तों के आधार पर आयोजित की जाएगी, हालांकि प्राधिकृत अधिकारी के पास किसी भी नियम और शर्तों को बदलने/परिवर्तित करने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोली जमा करने से पहले संपत्ति की प्रकृति और विवरण, स्थिति, किसी भी भार, इहसानिकार, प्रभार, वैधानिक बकाया आदि के बारे में किसी भी भार के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करें, उप–पंजीयक कार्यालय और राजस्व रिकॉर्ड/नगरपालिका रिकॉर्ड और सबंधित संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रासंगिक सरकारी रिकॉर्ड में खोजें और खुद को सतुष्ट करें। कृपया ध्यान दें कि बैंक/अधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार नीलामी के तहत संपत्ति/संपत्तियों /संपत्तियों की स्थिति/हैसियत/शीर्षक के संबंध में किसी भी तरह के गारंटी या कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता है। बिक्री/नीलामी पूर्णतया बिना किसी सहारा के आधार पर होगी।
26. यदि सभी लागतों के साथ बैंक की देय राशि, उनके द्वारा या उसके द्वारा किए गए खर्च, जो बैंक को स्वीकार्य हो सकते हैं, कर्जदार/गारंटर/ऋणकर्ता/ओं की ओर से किसी के लिए निर्धारित तिथि को या उससे पहले किसी भी समय अदा किए जाते हैं, तो नीलामी के लिए प्रस्तुत संपत्ति की बिक्री रद्द की जा सकती है। प्राधिकृत अधिकारी के पास किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है, यदि स्वीकार्य नहीं पाया जाता है या बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी को स्थगित/रद्द/परिवर्तित/बंद करने का बदलने का अधिकार सुरक्षित है और इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा।
27. प्रतिभूत परिसंपत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। यदि बैंक या उसकी ओर से किए गए सभी लागतों, प्रभारों और खर्चों के साथ बैंक की सर्वोदय राशि या सुरक्षित ऋण से अधिक राशि या इंटर–से विदित के बाद उपलब्ध बोली मूल्य से अधिक राशि, जैसा कि बैंक को स्वीकार्य हो सकता है, ऋणी/गारंटर/ऋणकर्ता की ओर से/की ओर से, उनके द्वारा पहचाने गए एजेंटों/खरीदारों/निवेशकों के माध्यम से भी नीलामी के लिए निर्धारित तिथि को या उससे पहले किसी भी समय, बिक्री या नीलामी की उसी तारीख को या बोली की औपचारिकताओं के पूरा होने से पहले/बाद में उपखात बोली लगाने वाले की